



प्रे.सं. शनिवार, शनिवार १८ जुलाई: स्थायी नदी में शनिवार सुबह एक अक्षांत योजना का राश मिनेस ने इलाके में सनसनी फैल गई धमी-जमालापर क्षेत्र में नदी किनारे कचरे के बीच शव फंसा हुआ देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के करीब दो घंटे बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। खेदे समय तक पुलिस के आने का इंतजार करने के बाद एक स्थानीय व्यक्ति

⇒ सोशांस पृष्ठ ३ पर

प्रेरणा भारती

!! नकारात्मक विचारों का आना तय है, परन्तु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हे कितना महत्व देते हैं। !!

सम्पादकीय.....

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा

इस बात को ढाई साल से ज्यादा हो चुके हैं जब केंद्र सरकार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जायेगा। कोर्ट ने कोई समयसीमा तो तय नहीं की, लेकिन उम्मीद थी कि यह वाजिब समयावधि के भीतर होगा और क्रमिक रूप से कदम उठाये जायेंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी-नीत सरकार ने इस मोर्चे पर कुछ नहीं किया है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसने समयसीमा के अभाव को राज्य-का-दर्जा अनिश्चितकाल के लिए टालने का लाइसेंस समझ लिया हैं। केंद्र द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद ऐसा हैं। जम्मू-कश्मीर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वादा किया और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसद के भीतर दोहराया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस निष्क्रियता के चलते जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों की श्रृंखला आयोजित करनी पडी, जिसका समापन २० जुलाई को जंतर-मंतर पर धरने के साथ होगा। उनकी और इस प्रांत की शिकायत जायज हैं। लोकप्रिय चुनाव के बाद भी केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा बनाये रखने से निर्वाचित सरकार एक अनिर्वाचित उप-राज्यपाल के अधीन हो जाती हैं जिसके पास नौकरशाही, पुलिस और अन्य संस्थाओं, पर अधिक अधिकार होता हैं। एक बार चुनाव हो जाने और सरकार बन जाने के बाद इस बंदोबस्त को जारी रखने का कोई सैद्धांतिक औचित्य नहीं हैं।

इस मामले में निष्क्रियता के लिए नई दिल्ली का तर्क घिसा-पिटा रहा हैं: झुसुरक्षाड़। पिछले साल के आखिर में, राज्य-का-दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर-जनरल ने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए इसी तर्क का इस्तेमाल किया। लेकिन इस दलील में कोई दम नहीं हैं। खुद सरकार का कहना हैं कि यह हमला सीमा पार से कराया गया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुकम्मल जवाब दिया। एक सीमा-पार उकसावे का इस बात से कोई तार्किक वास्ता नहीं हैं कि पूर्ण राज्य की शक्तियां सौंपने के लिए जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा किया जाए या नहीं। बल्कि, निर्वाचित नेताओं को स्थानीय शिकायतें दूर करने के लिए सशक्त बनाना ही वह तरीका हैं जिससे कोई राज्य-व्यवस्था चिंताओं को असंतोष में बदलने से पहले ही शांत कर देती हैं। गौरतलब हैं कि इसी असंतोष ने दशकों तक कश्मीर घाटी में उग्रवाद के विभिन्न दौर को हवा दी। केंद्र सरकार जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और यहां तक कि मणिपुर को संभाल रही हैं, उससे बडी अल्पसंख्यक आबादी वाले इन सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ हो रहे सलूक में एक चिंताजनक पैटर्न दिखता हैं। पूरे उत्तर, पश्चिम और अब पूर्व में अपने दबदबे को लेकर निश्चित भाजपा इन प्रांतों के नागरिकों की चिंताओं को तुच्छ मानती लग रही हैं। ऐसा नजरिया अदृद्शी हैं: जो शासन-व्यवस्था किसी सीमावर्ती क्षेत्र को राजनीतिक रूप से गौण मानती हैं, वह केवल अलगाव की भावना और गहरी करती हैं; और जल्द ही अस्थिरता दूसरी जगहों तक भी फैल जाती हैं और पूरी शासन-व्यवस्था को हिला देती हैं। ऐसा लगता हैं कि भाजपा राज्य-का-दर्जा मुद्दे को तब तक लटकाये रखने में ही खुश हैं जब तक कि राजनीतिक अंकगणित उसके पक्ष में निर्णायक ढंग से न झुक जाए। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के जरिए अंकगणित बदलने की कोशिश वह पहले ही कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट, संसद और जम्मू-कश्मीर की जनता से किये गये वादे को राजनीतिक हालात भाजपा के लिए सुविधाजनक होने के इंतजार में लटका कर नहीं रखा जा सकता।

जिंदगी स्क़्ती नहीं रिश्ता टूटने से

उषा जैन 'शीरी'

रिश्ते का टूटना दुखदायी होता है। संभलते हुए वक्त लगता है। जिन्दगी स्क़्ती नहीं है। समय के साथ घाव भी भरने लगते हैं और आप एक नया अध्याय खोलने को तत्पर हो जाते हैं. फिर से डेटिंग का सिलसिला शुरूहोने लगता है हालांकि इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना आसान नहीं। ढेर सी मानसिक शक्ति और साहस जुटाकर ही आप आगे बढ़ पाते हैं।पिछला चैटर क्लोज कर आगे का पृष्ठ खोलने से पहले आप लोगों को कैसे जतायेंगे कि आप नई शुरूआत के लिए तैयार हैं। यह इतना आसान नहीं। हो सकता है इस बीच किसी ने आप में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश भी की हो लेकिन आपका ख़्वा व्यवहार और अपने ही दुखों में लीन रहने की आदत देखते हुए वो पीछे हट गया हो। खोल से बाहर निकलें:-अब तक जो आपने अपने को एक खोल के भीतर कैद कर रखा था, इससे बाहर निकलें। किसी एक व्यक्ति के साथ ही जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जिन्दगी स्क़्ती नहीं। वो तो अनवरत चलती ही रहती है। यहां पर स्क़्ना मौत के समान होगा, इसलिए जीवन में रस लें, दिलचस्पी लें। दोस्ती के जरिए नये दोस्त बनाएं। सोशल बर्नें। पार्टीज, फंक्शंस वगैरह में जाने से न कतराएं। नया रिश्ता जोड़ने में झिझक न करें। यह न सोचें कि घरवाले, दोस्त, सहेली, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अब रिश्ते का टूटना पहले की तरह शर्मनाक नहीं माना जाता।

चेतावनी के साइन:- नये रिश्ते की शुरूआत सुखद हो सकती है लेकिन यहां सावधानी बरतनी भी ज़रूी है। बगैर सोचे समझे परखे किसी के साथ भी डेटिंग पर वक्त देना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। पहली बात तो यह है कि अपना सेल्फ एस्टीम कम न होने दें। किसी भी तरह के अपराध बोध से स्वयं को मुक्त रखें। अगर आपको अपने पिछले रिश्ते को लेकर किसी भूल का अहसास है भी तो भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प लें लेकिन पछतावे में अपनी ऊर्जा का क्षय न होने दें। मन में सोचें कि अगर दूसरे की भावनाओं में परिवर्तन आ गया है, प्रेमी ने बेवफाई दिखाई है तो उसमें

- ई० प्रभात किशोर

भारत का संविधान अपने नागरिकों को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, परन्तु सामाजिक भेदभाव के कारण, समाज के एक बड़े वर्ग का सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में अल्प प्रतिनिधित्व है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए जनता पार्टी सरकार के द्वारा १ जनवरी १९७९ को श्री बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग ने ३१ दिसंबर १९८० को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु यह कांग्रेस शासन के पूरे एक दशक तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। सन १९८९ में जब जनता दल सरकार सत्ता में आई, तो १३ अगस्त १९९० को केंद्र सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए २७ प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। रिपोर्ट से उल्लिखित है कि ब्रहिंदू और गैर-हिंदू दोनों श्रेणी के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ५२ प्रतिशत है। तदनुसार, केंद्र सरकार के तहत सभी पदों में से ५२ प्रतिशत का यथानुपात आरक्षण उनके लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। परन्तु यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय के उन निर्णयों के विरुद्ध होगा, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद १५(४) और १६(४) के तहत आरक्षण की कुल मात्रा ५० प्रतिशत से कम होनी चाहिए। इसे देखते हुए, पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाय कि अनु० जाति एवं जनजाति के लिए प्रावधानित आरक्षण २२.५ प्रतिशत में जोड़ने पर वह ५० प्रतिशत से नीचे रहे। इन कानूनी बाधाओं को देखते हुए, आयोग

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत में धर्मांतरण, यह विषय पिछले कुछ वर्षों में सामने आए अनेक प्रकरणों से कहीं अधिक व्यापक हो गया है। इसमें विदेशी फंडिंग, वैचारिक हस्तक्षेप, जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ती सक्रियता और नक्सली नेटवर्क से संभावित संबंधों जैसे गंभीर आयाम भी जुड गए हैं। बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दर्ज हालिया एफआईआर ने एकबार फिर इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खडा किया है।

यदि हम भारत का समग्र चिंतन करते हैं तो एक बात तय है कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय परंपराओं और हजारों वर्षों से विकसित सामाजिक संरचना से बनती है। विशेष रूप से जनजातीय समाज अपनी विशिष्ट आस्था, जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत के कारण भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग हैं। ऐसे समाजों में यदि बाहरी वैचारिक हस्तक्षेप योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो स्वभाविक है कि उसका प्रभाव धार्मिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक संतुलन और सामुदायिक विश्वास पर भी पडता है।

वस्तुत: बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर ने

ने केवल २७ प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की, भले ही उनकी जनसंख्या प्रावधानित अनुशंसा से दोगुनी हो। जिन राज्यों ने पहले ही ओबीसी के लिए २७ प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू कर दिया है, वे इसे अनुशंसा से अप्रभावित रहेंगे।“ न्यायालय के द्वारा ५० प्रतिशत सीलिंग की कानूनी बाध्यता के कारण आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए मात्र २७ प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की गई है, अन्यथा यह अनुशंसा जनसंख्या अनुपात के अनुसार यानी ५२ प्रतिशत होती। अगदी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए १० प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के लिए वर्ष २०१९ में, १०३वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीमा को बढ़ाकर ६० प्रतिशत कर दिया गया है। यही प्रक्रिया पिछड़े वर्गों को भी महज २७ प्रतिशत के स्थान पर ५२ प्रतिशत आरक्षण देने के लिए की जानी चाहिए थी, लेकिन खंडित दवे-कुचले तबके कभी भी सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं रहे । जनता दल एवं बाद की अन्य दलों की केंद्र सरकारों ने मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू नहीं किया । आयोग की अनुशंसायें केवल सरकारी सेवाओं (जो जनसंख्या के १ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं) के लिए नहीं हैं बल्कि समाज के सर्वगीण विकास के लिए हैं, ताकि एक निश्चित अवधि के बाद सभी नागरिक एक ही बेंच मार्क पर खड़े हो सकें। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा निम्नलिखित योजनाओं की अनुशंसा की गई है, जिनका क्रियान्वयन अभी प्रतीक्षित है:-

(१) एक खुली प्रतियोगिता में गुणगुण

आधार पर नियोजित पिछड़े वर्ग के

उम्मीदवारों को उनके २७ प्रतिशत

आरक्षण कोटा में समायोजित नहीं



किया जाना चाहिए।

(२) उपरोक्त आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति में भी लागू किया जाना चाहिए।

(३) आरक्षित कोटा जो भरा नहीं गया

है उसे तीन साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद अनारक्षित किया जाना चाहिए।

(४) सीधी भती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट ओबीसी के उम्मीदवारों को उसी तरह दी जानी चाहिए जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में दी जाती है। (५) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर प्रणाली उसी प्रकार से अपनाई जानी चाहिए जैसे वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में अपनाई जाती है।

(६) आरक्षण की उपरोक्त योजना केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी सभी भर्तियों पर लागू होनी चाहिए।

(७) सभी निजी क्षेत्र के उपक्रम जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, उन्हें उपरोक्त आधार पर कर्मियों की भती करनी चाहिए।

चर्च-नक्सल गठजोड़: क्या विदेशी फंडिंग के सहारे

भारत की सामाजिक जड़ों पर हो रहा प्रहार?



यदि किसी समुदाय की आस्था को कमजोर करके उसके स्थान पर नई वैचारिक पहचान स्थापित करने की रणनीति अपनाई जाती है तो यह स्वभाविक तौर पर सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करने का प्रयास है।अब यदि भारतीय संविधान के संदर्भ में इसे समझें तो हमारे लोकतांत्रिक समाज में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है किंतु वह दूसरे समुदाय की आस्था को अपमानित करने या योजनाबद्ध ढंग से सामाजिक विभाजन पैदा करने का माध्यम नहीं बन सकता, इसके लिए पूरी तरह से मनाही है बल्कि कहें कि इसे अपराध तक घोषित कर रखा है। इसके बावजूद देखने में बार-

बार यही आ रहा है कि चर्च पोषित संस्थाएं कन्वर्जेंट के खेल में लगी हुई हैं।

उदाहरण स्वस्थ आप इन बड़े मामलों को भी देख सकते हैं- भीमा कोरेगांव प्रकरण, फादर स्टैन स्वामी से जुड़े. आरोप, झारखंड का पथलगडी आंदोलन और ओडिशा में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड जैसे मामले वस्तुत: अलग-अलग घटनाएं भले हों किंतु इन सभी ने समय-समय पर यह प्रश्न अवश्य खडा किया कि क्या कुछ क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक और उग्रवादी नेटवर्क किसी स्तर पर एक-दूसरे के संपर्क में रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ?विदेशी फंडिंग का प्रश्न भी कम

महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) इसी उद्देश्य से बनाया गया कि विदेश से आने वाले धन का उपयोग पारदर्शी और घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो। यदि किसी संस्था द्वारा प्राप्त धन का उपयोग सामाजिक सेवा, शिक्षा या स्वास्थ्य के बजाय वैचारिक धुवीकरण, अवैध धर्मांतरण या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है तो यह स्थिति कानून का उल्लंघन होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है।भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। लेकिन यही संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और कानून के दायरे को भी समान रूप से महत्व देता है। इसलिए, धार्मिक स्वतंत्रता और संगठित धर्मांतरण के बीच की सीमा को स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का धार्मिक परिवर्तन उसकी स्वतंत्र इच्छा से होता है तो वह संवैधानिक अधिकार हैं लेकिन यदि उसके पीछे आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाव, विदेशी वित्तपोषण या वैचारिक अभियान काम कर रहे हों तो वह निश्चित तौर पर सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है,

खाने में स्वाद बढ़ाएं ऐसे

मिला लें।

करेले की कड़वाहट कम करने के लिए करेले बनाते समय उसमें थोड़ी सी भुनी पिसी मेथी डालें। कड़वाहट भी कम होगी और स्वाद भी अधिक आएगा।

अगर आप सलाद को नया लुक और स्वाद देना चाहती हैं तो उबला पास्ता या नूडल्स डाल दें। उन पर थोड़ा कटा टमाटर व चीज कददूकस कर सजाएं। सलाद नया लुक भी देगा और स्वाद भी अच्छा लगेगा।

कोल्ड कॉफी को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए आइस टैं में काफी पाउडर डाल कर आइस क्यूब जमाएं। कोल्ड काफी बनाते समय उसमें काफी क्यूल्स मिलाएं। अधिक मजा आएगा।

खिले हुए चावल बनाने के लिए चाहे नमकीन हों या उबले हुए, बनाने से पहले उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं।

भिंडी को अधिक क्रिस्पी बनाने के लिए भिंडी बनाते समय नींबू का रस मिलाएं।

स्टफ्ट आलू बनाने के लिए आलू

उबालते समय आलूओं की मात्रानुसार पानी में नमक डालें। आलू टूटेंगे नहीं।

पनीर की सब्जी बनाते समय पनीर से अधिक टमाटर मिक्सी में ब्लैंड कर डालें और एक चम्मच टोमेटो सास और मलाई फेंट कर डालें। पनीर बहुत स्वादिष्ट बनेगा।

मेवी वाली सब्जी में पिसा लहसुन पानी में थोड़ा।

घोलकर मसाले में डालें। लहसुन का फ्लेवर अच्छा आएगा।

नमकीन नींबू पानी बनाते समय उसमें जलजीरा पाउडर मिलाएं और साथ में महीन पिसा पुदीना भी डालें। स्वाद अच्छा लगेगा।

खीर बनाते समय चावलों को हल्का सा घी में भूनकर फुल क्रीम दूध मिलाएं

सामाजिक-शैक्षिक और आर्थिक उपायों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित किया जाना चाहिए।

(२) पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्यों में एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।

(४) अत्यंत पिछड़े वर्गों यथा-हिमाचल प्रदेश में गद्दी, महाराष्ट्र में नव-चौद, तटीय क्षेत्रों में मछुआरे, जम्मू एवं कश्मीर में गुर्जनों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए, परिसीमन के दौरान उनकी सघनता वाले क्षेत्रों को अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सहायता:-

राज्य सरकार द्वारा सभी विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा उसी तरह और उसी सीमा तक वित्तपोषित किया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में किया जाता है। पूरी योजना को केवल बीस साल (यानी एक पीढ़ी की अवधि) के बाद संशोधित किया जाना चाहिए। कम अंतराल पर कोई समीक्षा पिछड़े वर्ग की वर्तमान स्थिति और जीवन शैली पर अनुशंसाओं के प्रभाव का उचित आकलन संभव नहीं होगा।

आयोग की रिपोर्ट १९३१ की पिछली जगणगना के यथानुपात आधारित थी। २०२१ के बाद की आगामी जगणगना में जातिवार सर्वेक्षण और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की लंबे समय से जनता की प्रबल मांग हैं। इससे न केवल कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में असमानता को तेजी से दूर करने में भी मदद मिलेगी। (लेखक अभियंता और शिक्षाविद हैं)

यह तो सीधे-सीधे एक देश की संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति को ही बदल देना हैं !

अब इस नजरिए से देखें तो आज बेंगलुरु से शुरू हुई यह नई जांच के अनुरूप हो। यदि किसी संस्था द्वारा प्राप्त धन का उपयोग सामाजिक सेवा, शिक्षा या स्वास्थ्य के बजाय वैचारिक धुवीकरण, अवैध धर्मांतरण या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है तो यह स्थिति कानून का उल्लंघन होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है।भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। लेकिन यही संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और कानून के दायरे को भी समान रूप से महत्व देता है। इसलिए, धार्मिक स्वतंत्रता और संगठित धर्मांतरण के बीच की सीमा को स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का धार्मिक परिवर्तन उसकी स्वतंत्र इच्छा से होता है तो वह संवैधानिक अधिकार हैं लेकिन यदि उसके पीछे आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाव, विदेशी वित्तपोषण या वैचारिक अभियान काम कर रहे हों तो वह निश्चित तौर पर सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है, (लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)



तो खीर स्वादिष्ट और गाढ़ी बनेगी।

किसी भी खाने को सर्व करने से पहले मलाई को अच्छी तरह फेंट कर मोटी स्टील की छलनी में कड़छी से हिलाते हुए सर्विंग वाउल में सब्जी के ऊपर गार्निश करने से सब्जी सुन्दर भी लगती है और स्वाद भी अच्छा लगता है। (उर्वशी)

प्रेरणा भारती

प्रथम पृष्ठ का शेषांश.....

असम राज्य सूचना आयोग की सख्त कार्रवाई,...

तक मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा आयोग द्वारा जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और सुनवाई की निर्धारित तिथियों पर भी संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम का गंभीर उल्लंघन मानते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा २०(१) के तहत २० हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।आयोग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आदेश प्राप्त होने के ३० दिनों के भीतर ज़ुर्माने की राशि जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के पायलापूल निवासी एवं व्यवसायी राकेश सिंह ने ३० जुलाई २०२४ को सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत लखीपुर महकमा कार्यालय तथा उसके अधीन खाब एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारीयां मांगते हुए आवेदन किया था।निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उन्होंने प्रथम अपील जिला आयुक्त कार्यालय में दायर की। वहां से भी समय पर कोई उत्तर नहीं मिलने पर राकेश सिंह ने असम राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने अपील स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई शुरू की और २३ अप्रैल तथा ८ जून २०२६ को दो अलग-अलग तिथियां निर्धारित कीं। हालांकि दोनों ही सुनवाई में संबंधित अधिकारी अनुपस्थित रहे। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही आयोग के समक्ष कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए असम राज्य सूचना आयोग ने मेमो संख्या 575419/CCR/40/2024/19 दिनांक ३ जुलाई २०२६ के माध्यम से अधिनियम की धारा २०(१) के तहत २० हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि यद्यपि राकेश सिंह द्वारा दायर अपील का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन जुर्माने की राशि ३० दिनों के भीतर जमा नहीं होने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी आखिर क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। हालांकि सूचना आयोग के आदेश में दंड लगाने के कारणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सूचना उपलब्ध न कराने के पीछे के कारणों पर संबंधित अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।

लखीपुर विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की...

परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने तथा आम जनता को समय पर परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आवश्यक प्रशासनिक समन्वय तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष कंकन नारायण सिकिदार, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डोरोथी सुचियांग, एसीएस, सहायक आयुक्त पीयूष राज, आईएएस, जिला परिषद के उपाध्यक्ष देबज्योति बाउरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

संघ कभी सूर्यास्त नहीं देखता, सदैव चिरयुवा

दृष्टि और विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार व्यक्तिपूजा और व्यक्तिवाद के विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति उसके कार्यकर्ताओं की समान भागीदारी, अनुशासन और समर्पण में निहित होती है। इसी सोच के अनुरूप उन्होंने संघ की कार्यप्रणाली विकसित की, जिसमें सभी स्वयंसेवकों के लिए समान अवसर और समान सम्मान की भावना है।

प्रो. सिन्हा ने कहा कि डॉ. हेडगेवार के प्रत्येक संगठनात्मक प्रयोग का मूल उद्देश्य समाज का संगठन और मानव कल्याण था। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र और संकीर्ण पहचान के आधार पर विभाजित करने वाली प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती हैं। जब तक समाज इन विभाजनों से ऊपर उठकर स्वयं को एक रा्ट के रूप में नहीं देखेगा, तब तक एक सशक्त और संगठित भारत की निर्माण संभव नहीं होगा।राकेश सिन्हा ने सभी नागरिकों से जाति, अस्पृश्यता, क्षेत्रीयता और भाषाई भेदभाव जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर स्वयं को भारत माता की संतान मानने और सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में स्थायी परिवर्तन केवल सकारात्मक वैचारिक जागरण और सामाजिक संगठन के माध्यम से ही संभव है।अपने संबोधन में प्रो. सिन्हा ने कहा कि केवल बाहरी धार्मिक आक्रांकता या किसी संकट के कारण उत्पन्न एकता स्थायी नहीं होती। समाज की वास्तविक एकता उसके साझा सांस्कृतिक मूल्यों, पारस्परिक विश्वास और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शासन दो अलग-अलग संस्थाएं हैं तथा संघ की विचारधारा किसी भी सरकार या शासक की इच्छा के अनुसार संचालित नहीं होती, बल्कि वह अपने मूल सिद्धांतों और संगठनात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करता है।कार्यक्रम का संचालन उत्तर असम प्रांत के प्रचार प्रमुख किशोर शिवम ने किया। समापन सत्र में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग की अध्यक्ष प्रो. कल्पना बोरा ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे वैचारिक कार्यक्रम समाज और युवाओं के बीच संवाद तथा चिंतन की नई दिशा प्रदान करते हैं।

सोनाई नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से

शव को दोबारा नदी की धारा में बहा दिया। इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष है। उनका कहना है कि यदि पुलिस समय पर पहुंचती, तो शव की पहचान और प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया आसानी से शुरू की जा सकती थी। इधर, पिछले चार दिनों से लापता मोनिमरखाल चाय बागान क्षेत्र के निवासी प्रजा राजभर के परिजन भी शव की पहचान के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही शव को नदी में बहा दिया गया। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। घटना को लेकर पुलिस की आगे की कार्रवाई और जांच पर अब स्थानीय लोगों की नज़र टिकी हैं।

असम विश्वविद्यालय में सोमवार से समाहव्यापी लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशाला

प्रे . स . शिलचर, १८ जुलाई: असम विश्वविद्यालय में २० से २५ जुलाई तक ‘ जे ’ ड र सेंसिटाइजेशन, प 1 ~ श (POSH) अधिनियम एवं



महिला सशक्तिकरण‘ विषय पर समाहव्यापी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (खउउ) तथा मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (चचढउउ), असम विश्वविद्यालय चैप्टर द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला में देशभर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, प्रशासक एवं विषय-विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यशाला का उद्घाटन सत्र २० जुलाई को प्रातः १०:०० बजे विश्वविद्यालय के विपिन चंद्र पाल सेमिनार हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राजीव मोहन पंत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता उपस्थित रहें गीं। स्वागत भाषण आंतरिक शिकायत समिति की

अध्यक्ष प्रो. कक्की दत्ता चौधरी देंगी। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. प्रदीप किरण नाथ, एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो. रमैया बालकृष्णन, उपनिदेशक प्रो. अजय कुमार सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में प्रमुख वक्तओं एवं संसाधन विशेषज्ञों के रूप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलसचिव प्रो. एम. डी. महताब आलम रिवाजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मानवेन्द्र दत्ता चौधरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. शांता दत्ता डे, नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट (खड्डब) की संयुक्त निदेशक नमिता मलिक, जादवपुर विश्वविद्यालय की मालिक, जादवपुर की पूर्व कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता उपस्थित रहें गीं। स्वागत भाषण आंतरिक शिकायत समिति की बाबू सदस्य डॉ. अनिदिता बंबोषाध्याय तम्टा, एनआईटी दुर्गापुर की आईसीसी अध्यक्ष प्रो. सीमा सरकार, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल तथा सेवानिवृत्त शिक्षाविद् प्रो. विनोद नौटियाल अपने विचार साझा करेंगे। आयोजकों की ओर से डॉ. सोहन कुमार बेदाज्ञा ने बताया कि कार्यशाला में लैंगिक संवेदनशीलता, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम (झजडक) अधिनियम, महिला अधिकार, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभागियों का सक्रिय भागीदारी से यह कार्यशाला अत्यंत सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी।

डिब्रूगढ जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट बनी स्वास्थ्य सेवा की नई पहचान - स्वास्थ्य विभाग की उल्लेखनीय सफलता



डिब्रूगढ: (अर्णव शर्मा) १८ जुलाई : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम की मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) आज डिब्रूगढ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम बन चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग, डिब्रूगढ के सतत प्रयासों, दूरदर्शी योजना और जमीनी क्रियान्वयन के कारण MMU ने जिले के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक नई पहचान बनाई है। विशेषकर जिले के दूरस्थ, सीमांत और चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह सेवा बरदान साबित हो रही है। डिब्रूगढ जिले में वर्तमान में कुल २१ मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यरत हैं। इनमें से २० MMU जिले के १४७ चाय बागानों की लिए समर्पित हैं, जबकि १ MMU गैर-चाय बागान एवं अन्य वंचित क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है। इस व्यवस्थित मॉडल के कारण चाय बागान समुदाय को उनके द्वार पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाई है। प्रत्येक चरण में एक चिकित्सक, GNM नर्स, लैब तकनीशियन, नेत्र सहायक और फार्मासिस्ट की पूर्ण टीम तैनात है। यह इकाई एक ‘चलते-फिरते अस्पताल’ की तरह काम करती है, जहाँ जड़जड़ परामर्श, ड्रग्ग, घन्ट्ट, उडउ, एउअर्र जैसी प्रयोगशाला जांचें, नेत्र परीक्षण एवं परामर्श के साथ-साथ निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की जाती हैं। डिब्रूगढ स्वास्थ्य विभाग की योजना और निगरानी के परिणामस्वरूप चरण ने २०२४-२५ वित्तीय वर्ष में ३,९१,४०३ लोगों की, पिछले वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में ६३०० शिविरों का सफल आयोजन किया और ३,९४,४२८ लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग संभव हो पाई। चालू वित्तीय वर्ष में (अप्रैल ,२०२६- जून,२०२६) अब तक ९८,५०३ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें समय पर जांच और परामर्श के द्वारा कई गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान कर उपचार सुनिश्चित किया गया। MMU में स्क्रीनिंग के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा, माइकिंग और ऑडियो-विजुअल माध्यमों से जागृस्कता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति समझ और सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।IMMU के कारण डिब्रूगढ जिले की चाय बागानों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, एनीमिया और गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आया है। समय पर उपचार और जांच की सुविधा मिलने से रेफरल मामलों में कमी आई है और जिला अस्पतालों पर दबाव भी घटा है। इस प्रकार MMU ने केवल उपचार का माध्यम बनी है, बल्कि रोकथाम और जागृस्कता की दिशा में भी एक मजबूत स्तंभ सिद्ध हुई है।जिला स्वास्थ्य समिति, डिब्रूगढ ‘सबके लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य’ के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। चरण के माध्यम से विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि जिले का कोई भी नागरिक, चाहे वह कितने भी दूरस्थ क्षेत्र में क्यों न रहता हो, स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। यह पहल डिब्रूगढ स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता और सफल क्रियान्वयन का जीवंत उदाहरण है।

शिवसागर में ८०वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का रिव्यू



शिवसागर: (अर्णव शर्मा) १८ जुलाई : ८०वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए, शिवसागर जिला प्रशासन ने जिला कमिश्नर मुदुल यादव की अध्यक्षता में जिला कमिश्नर ऑफिस के सुकाफा कॉन्फ्रेंस हॉल में एक हाई-लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई।मीटिंग में जिले के ऑफिशियल स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम के पूरे इंतजामों का रिव्यू किया गया और समारोह को आसानी से, डिसिप्लिन में और शांति से कराने के लिए अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट की जम्मेदारियों को बताया गया।अधिकारियों को संबोधित करते हुए, जिला कमिश्नर ने मिलकर कोशिश करने की अहमियत पर जोर दिया और सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपनी-अपनी ड्यूटी ईमानदारी और कुशलता से निभाएं। मीटिंग में जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतीश चंद्र ठाकुरिया; एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लुकुमोनी बोरा, सोनोग्रिष्णा धरफलिया, मीनाक्षी परमे और गौरीप्रिया देवारी; इलेक्शन ऑफिसर अदिति नियोग; असिस्टेंट कमिश्नर अन्वेचा ठाकुर और नीलाक्षी भुयान शामिल हुए; अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों, सीनियर सिटिजन और आम लोगों के दूरेसे जाने-माने लोगों के साथ।जिला एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है कि वह सभी लॉजिस्टिक, सिक्वोरिटी, प्रोटोकॉल और सेंसेमोनियल अरेंजमेंट को काफ़ी पहले फाइनल कर लेगा ताकि यह पक्का हो सके कि ८०वां स्वतंत्रता दिवस पूरे शिवसागर ज़िले में सम्मान, देशभक्ति और लोगों की भागीदारी के साथ मनाया जाए।

असम के चराईदेउ में अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट के पास जंगली हाथी मरा हुआ मिला

चराईदेउ : (अर्णव शर्मा)

१८ जुलाई : असम के चराईदेउ जलि में अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट के पास शनिवार को एक जंगली हाथी रहस्यमयी हालत में मरा हुआ मिला, जिससे वाइल्डलाइफ.



अधिकारियों और स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई।शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक, हाथी खाने की तलाश में रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर निकला था, इससे पहले कि उसकी लाश जंगल के किनारे मिली। मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है। जानकारी मिलते ही, सोनारी पुलिस स्टेशन के और रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मौत का कारण पता लगाने के लिए जानवरों के डॉक्टर की टीम के पोस्टमॉर्टम करने की उम्मीद है, जबकि फॉरेस्ट अधिकारियों ने मौके से शुरुआती सबूत इकठ्ठा किए हैं। अधिकारियों ने बिजली का झटका, जह्र, या झंझन-वाइल्डलाइफ, ठक्काव के किसी भी दूसरे तरीके की संभावना से इनकार नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि मौत का आखिरी कारण फॉरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इस घटना ने एक बार फिर असम में झंझन-हाथी ठक्काव की बढ़ती चुनौती को सामने ला दिया है, जहाँ जंगली हाथी अक्सर इंसान की जाह में गड़बड़ और घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण खाने की तलाश में जंगल छोड़ देते हैं। चराईदेउ के अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट में हाल के तलाश में हाथियों के आने-जाने से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं, जिससे बार-बार मजबूत बचाव उपायों और वाइल्डलाइफ कॉरिडोर की सुरक्षा की मांग उठ रही है। फॉरेस्ट अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि पूरी जांच चल रही है और अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डिब्रूगढ में क्लाइमेट-रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग पर इनसेप्शन वर्कशॉप हुई

अधिकारियों को प्रोजेक्ट के मकसद, दायरे और लागू करने की स्ट्रेटेंजी के बारे में बताया गया। हिस्सा लेने वालों ने शहरी बाढ़ और गमी से जुड़े खतरों से निपटने के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों का भी रिव्यू किया और मिमिकर प्लानिंग और स्टेकहोल्डर की भागीदारी से डिब्रूगढ में क्लाइमेट रेजिलिएंस को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मीटिंग में मुख्य स्ट्रेकहोल्डर्स से इनपुट मांगे गए ताकि शहरी बाढ़ और बढ़ते तापमान के असर को कम करने के लिए असरदार और टिकाऊ स्ट्रेटेंजी बनाई जा सकें, साथ ही क्लाइमेट से जुडी चुनौतियों के लिए शहर की तैयारी को



अरुणाचल कैबिनेट ने ‘टीम अरुणाचल’ के १० साल पूरे होने का जश्न मनाया

प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में एक दशक के सुधारों की तरीफ की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ट्रिज्म और भलाई में हुई तरक्की पर जोर दिया गयों

ईटानगर:(अर्णव शर्मा) १८ जुलाई : अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में ‘टीम अरुणाचल’ के १० साल पूरे होने के मौके पर एकमत से एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें पूरे राज्य में शांति, सम्मान, खुशहाली और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के लिए अपना वादा दोहराया गया है।कैबिनेट ने



मुख्यमंत्री खांडू को इस अहम कामयाबी पर बधाई दी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भलाई और पूरी तरक्की के लिए काम करते रहने का वादा किया।प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर ४,३९९ दिन पूरे करने पर भी बधाई दी गई, जिससे वह लगातार चुने हुए कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। कैबिनेट ने २०१४ से नॉर्थईस्ट, खासकर अरुणाचल प्रदेश के विकास को तेज करने में लगातार मदद के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया।प्रस्ताव के मुताबिक, पिछले दशक में राज्य के लिए उम्मीदों और उम्मीदों का एक नया दौर शुरू हुआ है, जो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांतों और ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के विजन से गाइडेड है।पिछले दस सालों की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए, कैबिनेट ने कहा कि सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, छात्रों, सीनियर सिटिजन और समाज के दूरेसे तबकों की उम्मीदों को पूरा करने पर फोकस किया है। इसने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप, एंटरप्रेन्योरशिप, रिकल डेवलपमेंट, स्टार्टअप प्रमोशन, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, खेती, बागवानी और ट्रिज्म में की गई पहलों को इनक्लूसिव ग्रोथ में अहम योगदान देने का क्रेडिट दिया।कैबिनेट ने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में शानदार तरक्की देखी है, जो कभी स्ट्रेटेंजिक नजरअंदाज से प्रभावित क्षेत्र से भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। सेलिक्रेगन के हिस्से के तौर पर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन और दूसरे बड़े लोगों ने टीम अरुणाचल के दस साल लंबे सफ़र के पूरा होने पर एक खास यादगार पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। इस प्रस्ताव में विकास की रफ़्तार बनाए रखने और एक खुशहाल, सबको साथ लेकर चलने वाला और आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश बनाने की दिशा में काम करते रहने के सरकार के इादे को फिर से पक्का किया गया।

जोरहाट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए किशोर लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए

जोरहाट:(अर्णव शर्मा) १८ जुलाई : असम में किशोर लड़कियों को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने चाय बागानों और ग्रामीण समुदायों में हेल्थकेयर जागृस्कता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और



कई पहल शुरू की हैं।[जोरहाट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने, एडिशनल चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (पब्लिक हेल्थ), डॉ. भक्तिमय भट्टाचाजी के नेतृत्व में, जिले के चाय बागानों और पिछड़े गांवों के इलाकों में किशोर लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं।इस पहल का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह और टीनएज प्रेग्नेसी को रोकना है, साथ ही लड़कियों को छोटे पैमाने पर खेती-बाड़ी करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए बढ़ावा देना है।इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मदद से चाय बागानों और ग्रामीण इलाकों में १० किशोर लड़कियों के क्लब पहले ही बनाए जा चुके हैं। ये क्लब महिलाओं की हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, मेंटल हेल्थ और तंबाकू और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के नुकसानदायक असर पर रेगुलर अवेयरनेस सेशन करेंगे।इस पहल की एक खास बात मशरूम की खेती की ट्रेनिंग है, जिसे इसके मजबूत कमर्शियल पोर्टेशियल के लिए चुना गया है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनिंग से लड़कियों को रोजी-रोटी के मौके मिलेंगे, साथ ही कम्युनिटी को खाने लायक मशरूम की पहचान करने और जहरीली किस्मों के गलती से खाने से होने वाली मौतों को रोकने के बारे में भी जानकारी मिलेगी।मशरूम की खेती का प्रोग्राम असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (AAU) के टेक्निकल सपोर्ट से चलाया जा रहा है और हाल ही में सिचामारा टी एस्टेट में शुरू हुआ है। पहले ट्रेनिंग सेशन में एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब की लगभग ५० मेंबर्स ने हिस्सा लिया। यह प्रोग्राम सोशल वर्कर मिनाती पून नयना, सिचामारा टी एस्टेट हॉस्पिटल की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कनायथी महंता और सीनियर मैनेजर ऐयुत बरन चौधरी के सपोर्ट से ऑर्गनाइज किया गया था।अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी पक्का करने के लिए रिविआर और छुट्टियों के दिन क्लब की एक्टिविटीज, जिसमें हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन और एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग शामिल हैं, की जाएंगी। यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एखूड) २०२० के साथ भी जुडी हुई है, जो स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिटी एंजमेंट और प्रैक्टिकल फील्डवर्क को बढ़ावा देती है, साथ ही टीनएज लड़कियों के लिए अवेयरनेस, हेल्थ और रोजी-रोटी के मौकों को मजबूत करती है।जोहाट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का मानना १?है कि यह प्रोग्राम चाय बागानों और ग्रामीण समुदायों में गंभीर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हुए, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आर्थिक रूप से मजबूत युवातियों को बनाने में मदद करेगा।

अरुणाचल कैबिनेट ने हेल्थकेयर और वेलफेयर सर्विसेज को मजबूत करने के लिए CM CARES को मंजूरी दी

ईटानगर:(अर्णव शर्मा) १८ जुलाई : पब्लिक



हेल्थकेयर और सोशल सिक्वोरिटी को बढ़ाने के एक अहम कदम में, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पेमा खांडू कर रहे हैं, उच्च उअरुड (चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान रेंसिलिएंट, इष्टिटेसल एंड हेल्दी स्टेट) को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। यह एक खास पहल है जिसका मकसद पूरे राज्य में हेल्थकेयर तक पहुंच, किफायत और वेलफेयर सर्विसेज के तालमेल को बेहतर बनाना है।इस अम्बेला प्रोग्राम का मकसद मौजूदा हेल्थ और वेलफेयर स्कीमों को जोड़ना और उन्हें आसान बनाना है, ताकि यह पक्का हो सके कि नागरिकों, खासकर दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को समय पर और अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर के साथ-साथ बेहतर फाइनेशियल सुरक्षा मिले। इस पहल से सरकारी डिपार्टमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम के बीच बेहतर तालमेल के जरिए सर्विस में अंतर कम होने की उम्मीद है।उसी कैबिनेट मीटिंग में, सरकार ने मिशन सुरक्षा को भी मंजूरी दी, जो रोकथाम, इलाज, रीहबिलिटेशन और लागू करने के उपायों के जरिए ड्रग्स और नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए एक बड़ी पहल है। इसके अलावा, कैबिनेट ने टीबी को खत्म करने, बीमारी का जल्दी पता लगाने और बेहतर पब्लिक हेल्थ आउटरीच पर फोकस करते हुए २० दिन का राज्यव्यापी इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपेन शुरू किया। ये फैसले हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाने और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवन की पूरी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के कमिटमेंट को दिखाते हैं। कैबिनेट ने पूरे राज्य में पब्लिक सर्विस डिलीवरी और इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के मकसद से कई बड़े गवर्नंस और डेवलपमेंट सुधारों को भी मंजूरी दी।

डिब्रूगढ में बड़ा ड्रग भंडाफोड: पुलिस ने १.३५ kg हेरोइन, १४.०६ लाख रुपये कैश जप्त किया; एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

डिब्रूगढ: (अर्णव शर्मा) १८ जुलाई : ड्रग

तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, डिब्रूगढ पुलिस ने टिंगाखोंग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक सफल एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाया, जिसमें १०७ साबुन के डिब्बों में छिपाई गई १.३५ किलोग्राम हेरोइन और १४,०६,६०० रुपये कैश जप्त किया गया।यह ऑपरेशन खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद किया गया था। छापे के दौरान, पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप गाडी और आरोपी के घर की तलाशी ली, जिसमें गैर-कानूनी नारकोटिक्स तस्करों से जुड़ा संदिग्ध प्रतिबंधित सामान और कैश बरामद किया गया।पुलिस ने मुख्य आरोपी की पत्नी श्रीमती गुलाबी गोगोई को टिंगाखोंग पुलिस स्टेशन के तहत महामोरा कपीहुवा गांव से पकड़ा। हालांकि, मुख्य आरोपी, मनोज गोगोई (२९), जो मुदुल गोगोई का बेटा है, गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा और अभी फरार है। उसे ढूंढने और पकड़ने के लिए तलाशी शुरू कर दी गई है।नारकोटिक्स और कैश के अलावा, पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप और एक महिंद्रा स्कोर्पियो भी जप्त की, माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल गैर-कानूनी ड्रग के धंधे में किया गया था।जब्त की १०७ साबुन के डिब्बों में छिपाई गई १.३५ ड्रग्स हेरोइन, १४,०६,६०० रुपये कैश, एक बोलेरो पिकअप और एक महिंद्रा स्कोर्पियो शामिल हैं।डिब्रूगढ पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन जिले में नारकोटिक्स नेटवर्क को खत्म करने और ड्रग ट्रैफिकिंग के खतरे को रोकने के लिए उसके लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। इसमें शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और गैर-कानूनी धंधे के पीछे के बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

बेहतर बनाया जा सके। मीटिंग में डिब्रूगढ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई कमिश्नर

शिवानी जर्नाल, IAS, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारी, अलग-अलग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि, जनाग्रह के अधिकारी और दूसरे स्ट्रेकहोल्डर्स शामिल हुए। यह पहल डिब्रूगढ में ज़्यादा क्लाइमेट-रेजिलिएंट शहरी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है और यह असम की टिकाऊ और आपदा-रेजिलिएंट शहरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बड़ी कोशिशों से मेल खाती है।

अर्नव शर्माआरटीआई कानून के उल्लंघन पर लखीपुर के तत्कालीन एसडीओ (सिविल) पर २० हजार रुपये का जुर्माना।

प्रेरणा भारती

प्रथम पृष्ठ का शेषांश.....

श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से विक्रम-१ का सफल....

बूस्टर और ३डी-प्रिंटेड लिक्विड इंजन से बनाया गया है; विक्रम-१ भारत की बढती प्राइवेट-सेक्टर लॉन्च क्षमताओं को दिखाना है।- विक्रम-१ का प्रक्षेपण ‘मिशन आगमन’ के तहत १२ जुलाई से ४ अगस्त, २०२६ के बीच निर्धारित है। इस मिशन की सफलता भारत की स्वदेशी वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता और अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सरकारी सुधारों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करेगी।- इस मिशन के तहत कई ग्राहक पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ४५० किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इनमें स्काईस्ट का स्कोप उपग्रह, डीक्यूड्ड का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड, ग्रहा स्पेस का सोलारास एस-३ उपग्रह तथा कॉस्मोसर्व स्पेस की 'एम्ब्रेस' नामक गैरोटेटिक भुजा शामिल है। 'एम्ब्रेस' को अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को पकड़ने के लिए विकसित किया गया है।- विक्रम-१ की पहली उड़ान में दो विशेष वस्तुएं भी भेजी जाएंगीं।'कॉस्मिक ब्लूम', जो फूल के आकार की एक कलाकृति है और १८ कैंरेट सोने से बना एक सूक्ष्म रॉकेट। इस सूक्ष्म रॉकेट पर सी. वी. रमन, विक्रम साराभाई और डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की अत्यंत सूक्ष्म आकृतियां उकेरी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार चावल के एक दाने से भी छोटा है। यह भारत के महान वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक प्रयास है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को सक्षम बनाने वाले प्रमुख सुधार –भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार के नए अवसरों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं।भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति, २०२३ अधिसूचित की है, जिसके तहत गैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में भागीदारी की अनुमति दी गई है। इस नीति ने भारत में निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों के नए अवसर खोले हैं। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना, नए विचारों और उद्यमों को प्रोत्साहित करना तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है। साथ ही, यह नीति अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग एवं अन्वेषण के लिए वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करती है। ये सभी कदम मिलकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर हैं।

एकल-खिडकी अंतरिक्ष नियामक –भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र एकल-खिडकी एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष नीति, २०२३ के लागू होने के बाद इन-स्पेस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। यह संस्थानों को एक स्पष्ट और स्थिर नियामक ढांचा उपलब्ध कराता है तथा उद्योग की व्यापक भागीदारी को आसान बनाता है। साथ ही, यह इसरो की सुविधाओं, प्रौद्योगिकी और तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुंच उपलब्ध कराता है तथा पारदर्शी दिशा-निर्देशों के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। जून २०२६ तक इन-स्पेस ने ४,५०० से अधिक संस्थाओं का पंजीकरण, १३३ अनुमतियां जारी की हैं और १०६ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।इसके अलावा, फरवरी २०२६ तक इन-स्पेस ने वर्ष २०२५ के दौरान भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में १५ करोड.अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करने में सहायता की, जबकि शीर्ष १० स्टार्टअप को इसी मूल्य के पुष्ट वाणिज्यिक ऑर्डर प्राप्त हुए। जून २०२६ तक इन-स्पेस ने ११८ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को सुगम बनाया। १८९ संयुक्त परियोजना कार्यव्यवन्धन योजनाओं, प्रौद्योगिकी साझेदारी समझौतों और व्यावसायिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर कराए, जिससे प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण और उद्योग के बीच सहयोग को नई गति मिली। इन-स्पेस सीड फंड योजना: यह योजना अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र आवेदकों को एक करोड.रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय सहायता के साथ-साथ मेंटरशिप, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। यह योजना कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

१,००० करोड.रुपये का वेंचर कैपिटल (वीसी) कोष: इन-स्पेस के तहत स्थापित इस वेंचर कैपिटल कोष का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह निधि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत उभरते स्टार्टअप को शुरुआती चरण में पूंजी उपलब्ध कराती है। साथ ही, यह घरेलू अंतरिक्ष स्टार्टअप के उत्पादन को समर्थन देने और इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने का भी माध्यम है। इस पहल का लक्ष्य अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पाँच गुना बढ़ाना है। यह फंड वित्त वर्ष २०२५-२६ से २०२९-३० तक पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष १०० करोड.रुपये से २५० करोड.रुपये तक का निवेश किया जाएगा।५०० करोड.रुपये का प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष (टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड-टीएफएफ): इन-स्पेस द्वारा शुरू किए गए इस कोष का उद्देश्य गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विकसित स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देना है। यह प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक रूप से सफल उत्पादों में बदलने में भी सहायता करता है। इस योजना के तहत स्टार्टअप और एमएसएमई को परियोजना लागत का ६० प्रतिशत तक तथा बड़ी कंपनियों को ४० प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम २५ करोड. रुपये तक की सहायता प्रदान की जा सकती है।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का व्यवसायीकरण : न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) भारतीय अंतरिक्ष नीति, २०२३ के तहत न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है। एनएसआईएल वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर अंतरिक्ष प्रणालियों का निर्माण और अधिग्रहण करती है तथा सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को पेंड-टू-एंड अंतरिक्ष समाधान उपलब्ध कराती है। यह पीएसएलवी के उत्पादन, छोटे उपग्रहों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष उत्पादों एवं स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियों के विपणन तथा उपग्रह सेवाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है। पिछले कुछ वर्षों में एनएसआईएल के राजस्व में दस गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में उसकी बढ़ती वाणिज्यिक उपस्थिति को दर्शाती है। दिसंबर २०२५ तक इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के ७० से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से उद्योगों को तकनीक उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके व्यावसायीकरण को गति मिली। वहीं, जुलाई २०२६ तक एनएसआईएल ने कुल १४१ उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिनमें १३८ अंतरराष्ट्रीय /ग्राहक उपग्रह और ३ भारतीय उपग्रह शामिल हैं। यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भारत की एक विश्वसनीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में स्थिति को और मजबूत करती है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को अधिक उदार और निवेशक-अनुकूल बनाया गया है। नई नीति के तहत उपग्रहों के निर्माण और संचालन में ७४ प्रतिशत तक, प्रक्षेपण यान और स्पेसपोर्ट में ४९ प्रतिशत तक तथा उपग्रहों के पुर्णों और उप-प्रणालियों के निर्माण में १०० प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इस नीति से निवेश बढ़ने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कारोबार करना और अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

सैंटैलाइट का निर्माण और -अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण। सैंटैलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए कंपोनेंट्स और सिस्टम/सब-सिस्टम का निर्माण करने वाली

सुधार एक सशक्त, प्रतिस्पर्धी और गतिशील अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इनसे नवाचार, उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, आर्थिक विकास को गति मिल रही है और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है।नीति से प्रगति तक:-सरकार के सुधारों ने भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और वाणिज्यिक अवसरों के नए द्वार खोले हैं। इन सुधारों के परिणामस्वरूप प्रक्षेपण सेवाओं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। अक्टूबर २०२२ में एनएसआईएल ने भारत का पहला समर्पित वाणिज्यिक एलवीएम-३ मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के तहत वनवेब के ३६ उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया, जिससे वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत हुई।नवंबर २०२२ में 'मिशन प्रारंभ' के तहत विक्रम-एस का प्रक्षेपण किया गया। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट और इन-स्पेस से अनुमोदित देश का पहला निजी प्रक्षेपण था। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन में सेंसर से लैस तीन ग्राहक पेलोड भेजे गए, ताकि भविष्य के कक्षीय मिशनों के लिए आवश्यक प्रक्षेपण तकनीकों का परीक्षण किया जा सके।

मई २०२४ में अग्रिकुल कॉसमॉस श्रीहरिकोटा स्थित भारत के पहले निजी प्रक्षेपण परिसर 'धनुष' से रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली पहली गैर-सरकारी संस्था बनी। इस मिशन में दुनिया के पहले एकल-खंड (सिंगल-पीस) ज़ि-आयामी मुद्रित अर्ध-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का भी सफल प्रदर्शन किया गया। इन-स्पेस ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह (अर्थ ऑब्जर्वेशन सैंटैलाइट कॉन्टेलेशन) के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मंजूरी दी है। इस परियोजना का नेतृत्व पिक्सेल कर रही है, जबकि ध्रुव स्पेस, सैटयोर एनालिटिक्स इंडिया और पिक्ससाइट स्पेस इसके साझेदार हैं। इस पहल का उद्देश्य कृषि, आपदा प्रबंधन, जलवायु निगरानी और शहरी नियोजन जैसी सेवाओं को सशक्त बनाना है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को भी नई गति मिली है। फरवरी २०२६ में इन-स्पेस ने ५११ करोड.रुपये की लागत पर १० वर्षों के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) की प्रौद्योगिकी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को हस्तांतरित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उद्योग के माध्यम से इसके उत्पादन और प्रक्षेपण सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं, वेलाटिक्स प्युरोस्पेस ने डीआरडीओ के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत विकसित स्वदेशी हरित प्रणोदन प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया।

इन कार्यक्रमों ने स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया है और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे की राह:-सरकार द्वारा किए गए सुधारों और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष नीति, २०२३, उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और विशेष वित्तीय सहायता योजनाओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को नए प्रतिभागियों के लिए खोल दिया है। इन सुधारों ने एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जिसमें तेजी से विकसित होते स्टार्टअप, स्वदेशी नवाचार और वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार शामिल है। 'मिशन आगमन' के तहत विक्रम-१ का प्रस्तावित प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की बढ़ती क्षमता, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का भी प्रतीक है। इसरो के नेतृत्व में आरंभ हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो रही है, जो सरकार के सुधारों की सफलता को रेखांकित करती है। निरंतर नीतिगत समर्थन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और तकनीकी नवाचार के बल पर भारत वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर रहा है तथा भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सौजन्य अंतरिक्ष विभाग

अन्ना हजारे की केंद्र को दोटूक सलाह, सोनम वांगचुक की मांगों पर फैसला करो देश को अनिश्चितता में मत रखो

नई दिल्ली. (एजें) १८ जुलाई :

(जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों के पैरोकार सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई हैं. अनशन के २१वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक की सहनशक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और यदि मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं तो साफ तौर पर ‘हां’ या ‘ना’ कह देना चाहिए. अन्ना हजारे का यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए वांगचुक को सफ़्दरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उनके समर्थकों ने इसे जबरन हिरासत में लेने जैसा कदम बताया है.सोनम वांगचुक पिछले २१ दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनका मुख्य अग्रह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है. वांगचुक का कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है.

उन्के आंदोलन को कबड़ छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों का समर्थन भी मिल रहा है.शनिवार को दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को सफ़्दरजंग अस्पताल पहुंचाया. पुलिस का कहना है कि यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है. अदालत ने वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. पुलिस के अनुसार चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया ताकि उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जांच और आवश्यक उपचार किया जा सके.

हालांकि वांगचुक के समर्थकों और आंदोलन से जुड़े लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों का आरोप है कि पुलिसकमी सामान्य कदमों में जंतर-मंतर पहुंचे और स्वयं को मेडिकल टीम का सदस्य बताकर आंदोलन स्थल में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने स्वयंसेवकों को हटाकर वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की. समर्थकों का आरोप है

काछाड.के रजिस्ट्री कार्यालयों पर सेवा सेतु की सेवाओं में देरी कराकर आवेदकों को परेशान करने का आरोप

प्रे.सं.शिलचर, १८ जुलाई : सेवा सेतु पोर्टल और एआरटीपीएस पोर्टल को इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि नागरिक आवेदन के १० दिनों के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करें और निर्धारित समय के बाद देरी होने पर संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन काछाड.के जिला सब रजिस्ट्रार कार्यालय और डिप्टी सब रजिस्ट्रार कार्यालय के खिलाफ इस व्यवस्था को नाकाम कर काम में देरी करने और जिम्मेदारी से बचने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतों के अनुसार कार्यालय के बगल में स्थित पब्लिक पैसिलिटेशन सेंटर के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके यह काम किया जा रहा है, जहां आवेदकों से कहा जा रहा है कि १००० से २००० रुपये देने पर २ दिन में काम हो जाएगा, और जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनसे आवेदन के समय पहले ही दी गई जानकारी के लिए भी बार बार अनावश्यक सवाल पूछे जा रहे हैं। यह भी आरोप है कि आवेदन करते समय आवेदक के अपने फोन नंबर के बजाय पीएफसी अपना नंबर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण कार्यालय से आने वाले सभी सवाल फिर से पीएफसी के माध्यम से जाते हैं और जवाब नहीं दिए जाने पर १० दिन बीत जाने के बाद भी १० दिन की जवाबदेही का नियम लागू नहीं किया जा पाता है। इसे जवाबदेही से बचने और आम जनता को परेशान करने की जानबूझकर की गई चाल बताया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि सेवा सेतु जैसी अच्छी पहल के बावजूद इस तरह की प्रथाएं पारदर्शिता को कमजोर कर रही हैं और काछाड में बुनियादी रजिस्ट्री सेवाएं लेने वाले आम लोगों को परेशानी हो रही है। समस्या को और बढ़ाने वाली बात यह है कि पछेसी जिले हाइलाकांदी और श्रीभूमि में पहले ही धरित्री पोर्टल एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के रूप में लागू हो चुका है, जहां लोग जमाबंदी, ई खजाना और अन्य भूमि दस्तावेज ऑनलाइन बिना कार्यालय जाए प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से काछाड जिला अभी तक धरित्री के दायरे में नहीं आया है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भूमि रिकॉर्ड के लिए कार्यालय दर कार्यालय दौड़ना पड़ रहा है। इस गठजोड़ को तोड़ने और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों ने मांग की है कि रजिस्ट्री कार्यालयों के पास काम करने वाले पीएफसी कर्मियों का तुरंत तबादला किया जाए या उन्हें रोटेशन के आधार पर अलग अलग स्थानों पर भेजा जाए ताकि कोई विशेष स्वार्थ समूह न बन सके। बराक घाटी के अग्रणी निजी स्वयंसेवी संगठन ग्राम उन्नयन ओ समाज सेवा संघ ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है और प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि काछाड में सेवा सेतु पोर्टल और धरित्री पोर्टल को पारदर्शी तरीके से जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि नागरिकों को सुविधा पारदर्शिता और राहत मिल सके।

बरसात के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग २७ पर यातायात पूरी तरह ठप

गुवाहाटी, १८ जूलाई (हि.स.)।

गुवाहाटी के बाहरी इलाका जोराबाट में शुक्रवार की दोपहर बाद महज आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बरसात की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग २७ पर भारी जलजमाव हो गया। जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गई। बरसात के बाद जोराबाट में स्थित फ्लाईओवर के नीचे भारी जल जमाव हो गया।जोराबाट के अलावा ११ माइल, १० माइल ९ माइल, ८ माइल आदि इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग २७ पर भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई । जिसकी वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन जाम में फंस गए। स्थानीय लोगों की माने तो जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या मेघालय में हो रही अवैध पहाड़ों की कटाई है। पहाड़ों की कटाई की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने नाले पाछे की लाल मिट्टी से पूरी तरह भर गया है। वहीं मेघालय की ओर किसी भी प्रकार की नाले की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से सारा पानी सड़क पर आ जाता है।पहली बार इस तरह के जल जमाव की समस्या सन २०१६ में उत्पन्न हुई। जब फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का काम प्रारंभ हुआ। वहीं जोराबाट तीनाली इलाके में बनाए गए फ्लाईओवर के नीचे पानी बहने वाला पुल काफी नीचे है। जिसकी वजह से जोराबाट तीनाली में हल्की सी बरसात के बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है । जल जमाव की वजह



कि यह पूरी प्रक्रिया उनकी सहमति के बिना अपनाई गई और इसे जबरन कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए.आंदोलन से जुड़े.संगठन के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल स्वास्थ्य की निगरानी करने के निर्देश दिए थे, न कि किसी प्रकार की जबरन चिकित्सीय कार्रवाई की अनुमति दी थी. उनका कहना है कि वांगचुक की नियमित रूप से मेडिकल जांच की जा रही थी और उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से साझा भी की जा रही थी. ऐसे में पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाना अदालत के आदेश की गलत व्याख्या और अमानना के समान है. इस संबंध में कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है.घटनाक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि आंदोलन स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के गश्त पुलिस ने सख्ती बर्ती. कुछ छात्रों ने लाठीचार्ज किए जाने का भी दावा किया. हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों की

आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून और अदालत के निर्देशों के अनुसार की गई तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए.इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी गंभीर मुद्दे का समाधान बातचीत से ही निकलता है. यदि सरकार वांगचुक की मांगों से सहमत नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बतानी चाहिए, लेकिन लंबे समय तक किसी आंदोलनकारी को अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी सहनशक्ति की परीक्षा लेने के बजाय सकारात्मक संवाद शुरूकरना चाहिए.अन्ना हजारे की यह अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वर्ष २०११ में उन्होंने स्वयं लोकपाल कानून की मांग को लेकर दिल्ली में ऐतिहासिक अनशन किया था. उस आंदोलन ने तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पर व्यापक राजनीतिक दबाव बनाया था और पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन का स्वस्थ ले लिया था. ऐसे में हजारे का वर्तमान बयान सरकार और आंदोलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश माना जा

रहा है.

इस बीच वांगचुक की पत्नी ने भी सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी सहमति के बिना किसी प्रकार का चिकित्सीय उपचार नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि यदि वांगचुक की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए संबंधित लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. इस बयान के बाद पूरे मामले ने और अधिक संवेदनशील रूप ले लिया है.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोमम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ता जा रहा है. यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं.फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में हैं. उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, जबकि दूसरी ओर उनके समर्थक आंदोलन जारी रखने और सरकार से औपचारिक वार्ता शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं. अब संयुकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है कि वह अन्ना हजारे की सलाह को कितना महत्व देती है और क्या वांगचुक की मांगों पर संवाद की पहल करती है या नहीं.

होजाई महिला शाखा द्वारा बाबा जगन्नाथ शोभायात्रा में भक्तों को शीतल पेय जूस वितरण



होजाई १७ जुलाई–मारवाडी सम्मेलन, होजाई महिला शाखा द्वारा बाबा जगननाथ की शोभायात्रा के दौरान हजारों भक्तों को शीतल पेय एवं जूस आदि का वितरण किया।स्थानीय इस्कान मंदिर द्वारा आयोजित उक्त शोभा यात्रा जब भीमसरिया रोड से गुजर रही थी तब शाखा द्वारा भक्तों हेतु शीतल पेय एवं जूस आदि का वितरण किया।उक्त अवसर पर सरिता सारावगी मंजू भीमसरिया राधा सारावगी ईशु भीमसरिया अनिता सारावगी रितु सारावगी नीतू मोर पिंकी सारावगी कबिता सारावगी योगिता सारावगी नीमा भीमसरिया रेखा भीमसरिया ललिता भीमसरिया खुसबू भीमसरिया प्राची सारावगी किशिका सारावगी आदि सदस्य उपस्थित थीं।भक्तों ने उक्त कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की।कार्यक्रम को सफल बनाने में आशीष सारावगी का विशेष सहयोग रहा।

फकीरग्राम: बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा करियर काउंसलिंग और व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन



कोकराझार, १८ जुलाई: बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन (BSU), फकीरग्राम कौकमिटी के तत्वावधान में आज क्षेत्र के छात्र-छात्राई के भविष्य को दिशा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संगठन की ओर से आयोजित 'समर कोचिंग कैम्प' का हिस्सा है।?इस कार्यशाला में फकीरग्राम कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. हसमत अली ने बतौर संसाधन व्यक्ति (Resource Person) भाग लिया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कक्षा १०वीं के विद्यार्थियों को सही करियर चुनने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करना है।?कार्यक्रम की स्पर्ेखा: आज शनिवर की ?सुबह १०:१५ बजे: चितला हाई स्कूल में 'करियर काउंसलिंग' पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। सुबह ११:१५ बजे: जोगदोई हाई स्कूल में 'व्यक्तित्व विकास' (इशारीपरश्वर्री जॉशिश्रेणिशीपी) विषय पर व्याख्यान संचन हुआ। प्रोफेसर डॉ. हसमत अली के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने और जीवन कीशाल विकसित करने में काफी मदद मिलेगी।

असम कृषि विश्वविद्यालय की पहल: तेलिपाड़ा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में बीज और रोपण सामग्री का वितरण

योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपनी जमीन के दस्तावेजों को अद्यतन (अपडेट) रखने की सलाह दी।?इस अवसर पर बीटीसी के कृषि विभाग के निदेशक बी.बी. नार्जरी तथा विधायक शोभा राम बसुमतारी और अशरफुल इस्लाम शेख ने भी उपस्थित किसानों को संबोधित किया और उन्हें कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया।?कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन विशेषज्ञ डॉ. मुजाहरुल इस्लाम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कामेश्वर दास के अलावा जेडआरएस और केवीके के कई अधिकारी और सैकड़ों स्थानीय किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और विभिन्न रोपण सामग्री वितरित की गई।

ये दोस्ती है कमाल की!

बाघ के बच्चे के साथ अंजना

अमेरिका के एक अभयारण्य में रहने वाली चिम्पैंजी है अंजना। वह इतनी दयालु है कि उसने बहुत से जानवरों के बहुत से अनाथ बच्चों को अपनाया है। अब वह मां की तरह एक बाघ के बच्चे की देखरेख कर रही है और उसकी अठखेलियों में खुश भी हो रही है। वैसे चिम्पैंजी काफी बुद्धिमान और समझदार होते हैं और वे अपने साथ रहने वालों का भी ख्याल रखते हैं।



थेंबा का साथी एल्बर्ट



मां के मर जाने से नन्हा थेंबा (हाथी) बहुत दुखी हुआ और कई दिनों तक इसका शोक मनाता रहा। दक्षिण अफ्रीका के एक अभयारण्य में लाए जाने के बाद भी उसने खाना-पीना छोड़ रखा था। इसी दौरान उसे एल्बर्ट नाम की भेड़ के रूप में एक अच्छा दोस्त मिला। जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। खेलने के साथ दोनों झपकियां भी साथ ही लेते। नए दोस्त ने इतनी खुशियां दीं कि थेंबा अपने दुख भूल गया और फिर से खाना-पीना शुरू कर दिया।

बालू-लियो और शेर खान की तिकड़ी



शेर खान दरअसल शेर नहीं, बल्कि एक बाघ है और उसके साथ बालू नाम का भालू और लियो नाम का शेर

है। इन तीनों के साथ इनके मालिक ने बुरा सलूक किया था, जिस कारण बालू को चोट भी लग गई। इस मुश्किल की घड़ी में ये एक-दूसरे का सहारा बन गये और अब अमेरिका के एक अभयारण्य में ये अपना सारा वक्त साथ ही गुजारते हैं।

दुश्मन के भी दोस्त बनो

अमित लगातार कोशिश करता था कि किसी भी तरह करण को नीचा दिखा सके और दूसरे बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ा सके। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद करण अपनी पढ़ाई में और बेहतर होता जा रहा था। चाहे बात पढ़ाई की हो या खेल की, करण हर किसी में बाजी मारता और हर जगह उसकी खूब तारीफ होती। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमित को नीचा देखना पड़ा और वह बदल गया।

बहुत पहले की बात है। एक गांव था राजनगर। वहां पर करण नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का स्वभाव का बहुत अच्छा था। पढ़ाई में भी होशियार था। वह बहुत आज्ञाकारी और अपने मां-बाप का कहना मानता था। स्कूल में वह ज्यादातर बच्चों की तुलना में होशियार था। स्वभाव से वह विनम्र था और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसके स्कूल में चाहे उससे बड़े लड़के हों या कि छोटे, सभी उसे पसंद करते थे। लेकिन इस कारण बहुत से लड़के करण से जलते भी थे। करण की ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था, जिसका नाम था अमित। अमित पढ़ाई में तेज नहीं था। उसका स्कूल में खेलने में बहुत मन लगता था। वह अपने माता-पिता की बात नहीं सुनता था और उनसे रूखे तरीके से बात करता था। अपनी क्लास के लड़कों को वह चिढ़ाया करता था। यहां तक कि करण को भी वह खूब परेशान करता था। वह लगातार कोशिश करता था कि किसी भी तरह करण को नीचा दिखा सके और दूसरे बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ा सके। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद करण अपनी पढ़ाई में और बेहतर होता जा

रहा था। चाहे बात पढ़ाई की हो या खेल की, करण हर किसी में बाजी मारता और हर जगह उसकी खूब तारीफ होती। अपने आठवें जन्मदिन पर करण को अपने पिता की तरफ से गिफ्ट के तौर पर एक सुंदर सा पेन मिला। करण स्कूल में नोट्स लिखने के लिए वह पेन ले जाने लगा। वह पेन दिखने में तो सुंदर था ही, लिखता भी तेज था। जब अमित ने करण का पेन देखा तो उसे बहुत जलन हुई। अमित ने नजरें तिरछी करके करण से पूछा, 'यह पेन तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे खरीदा है?' 'नहीं, मुझे यह पेन मेरे मम्मी-पापा ने बर्थ डे गिफ्ट में दिया है।' करण ने जवाब दिया। इस बात से अमित का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। अपने माता-पिता से वह खुद इतना बुरा सलूक करता था कि अब तक उसे उनसे शायद ही कोई गिफ्ट मिला हो। जब लंच का वक्त हुआ, तो उसने करण का पेन चुराने का फैसला कर लिया। जब हर कोई लंच के लिए बाहर निकल गया, तो अमित ने चुपके से करण के बैग से पेन चुरा लिया। इसके बाद उसने पेन अपने बैग में छिपा लिया और लंच करने बाहर चला गया। जब करण वापस लौटा तो उसे बैग में अपना पेन नहीं मिला। उसने अपने टीचर को इस बारे में बताया। इसके बाद पूरी क्लास में पेन खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। तब टीचर ने क्लास के मॉनीटर से कहा कि वह सबके बैग की तलाशी ले। जल्द ही अमित के बैग से पेन मिल गया। उसे गुस्से से देखते हुए टीचर ने पूछा, 'अमित, पेन तुम्हारे बैग से निकला है, इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है?' अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोला। जब करण ने अमित को रोते हुए देखा, तो उसे अमित पर दया आ गई। उसके दिल में अमित के लिए कोई गिला-शिकवा नहीं था। उसने टीचर से कहा कि उसका खोया हुआ पेन वापस मिल गया है, अब वे अमित को सजा न दें। करण के इन शब्दों ने अमित की आंखें खोल दीं। वह हमेशा करण को परेशान करता था, लेकिन करण ने हमेशा उससे अच्छा व्यवहार किया। इस समय उसे एहसास हो रहा था कि करण कितना अच्छा लड़का है। उसने तुरंत करण और क्लास टीचर से माफी मांगी। इसके बाद करण और अमित दोस्त बन गए। फिर तो अमित का व्यवहार बदल गया और सभी उसे पसंद करने लगे। करण को अपने नए दोस्त पर नाज था।



हंसने वाला कोका

साथियों, क्या तुमने ऑस्ट्रेलिया के हंसने वाले कोका के बारे में सुना है? आजकल ऑस्ट्रेलिया में यह खूब चर्चित हो रहा है। हंसने वाले कोका का दरअसल राज यह है कि इसका मुंह इस तरह का बना होता है, मानो खुशी से हंस रहा हो। छोटे चूहे जैसा यह जानवर आजकल ऑस्ट्रेलिया में पर्यटकों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह बेहद सेल्फी फ्रेंडली जानवर है। इसके साथ सेल्फी आती भी बड़ी मस्त है। इसकी स्माइलिंग वाले जबड़े की बनावट के कारण कुछ समय पहले इसे दुनिया के सबसे खुश जानवर की उपाधि भी मिल चुकी है। कोका वैसे तो एक साथ रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जंगलों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट आइलैंड पर ये खूब पाए जाते हैं।

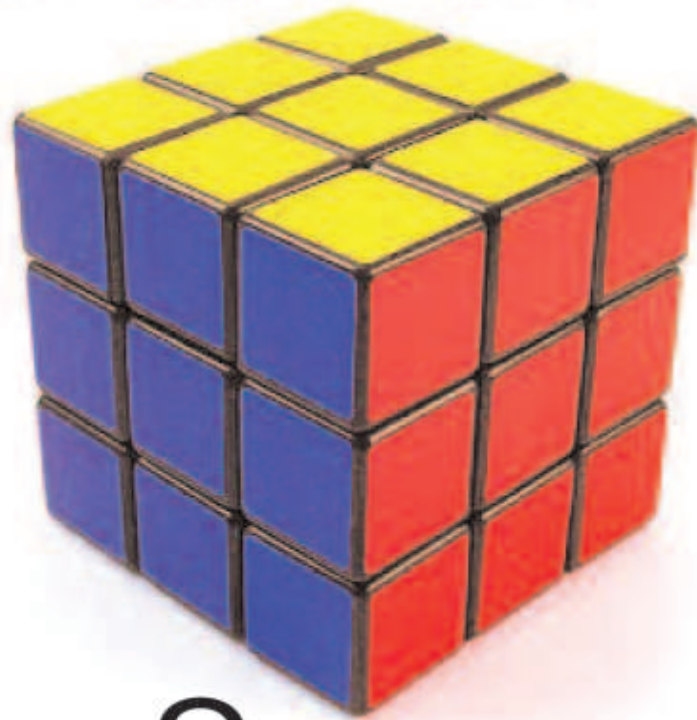


तुमने वह कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक राजा ने मक्खियों को उड़ाने की नौकरी एक बंदर को दी थी। एक दिन राजा की नाक पर बैठी मक्खी को उस बंदर ने डंडे से ऐसा भगाया कि राजा की नाक ही टूट गई। उसके बाद राजा ने ऐसे दोस्तों से तौबा कर ली थी। कुछ ऐसा ही माजरा हुआ है दक्षिण जापान के एक दूर के द्वीप पर। वहां पर अधिकतर मछुआरे रहते हैं। बेचारों ने काफी समय पहले एक ऐसे दोस्त से दोस्ती कर ली, जो अब उनकी जान की मुसीबत बन गया है। दक्षिणी जापान के

एक है कैट आइलैंड

आओशिमा नामक द्वीप पर मछुआरों की दोस्त बनकर आई बिल्लियां अब संख्या में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जिधर नजर घुमाओ, बिल्लियां ही बिल्लियां नजर

आती हैं। ये इतनी ज्यादा हो गई हैं कि यहां हर एक आदमी पर छह बिल्लियों का अनुपात बन गया है। बेचारों इस द्वीप के रहने वाले। हर वक्त उन्हें भगाते ही रहते हैं। कुछ उन्हें खाना भी खिलाते हैं। कुछ वर्षों पहले जब यहां चूहे बहुत ज्यादा हो गए थे और वे आए दिन मछुआरों की नाव काटने लगे, तो बिल्लियों को इस द्वीप पर लाया गया। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां हैं। इस द्वीप पर कुछ बुजुर्ग और युवा ही रहते हैं। बाकी सभी बड़े शहर चले गए हैं। अब यहां इतनी बिल्लियां हैं कि कोई रेस्टोरेंट या खोमचा नहीं खोला जा सकता। यहां केवल इस 'कैट आइलैंड' को देखने आने वालों को लाने-ले जाने वाली मोटरबोट ही ज्यादा दिखती है। हालांकि कुछ लोगों को इस द्वीप पर बिल्लियों को देखने में खूब मजा आता है।



रुबिक क्यूब्स का तोड़ा रिकॉर्ड

अगर इंटेलिजेंट होने की बात आती है, तो रुबिक क्यूब्स में महारत की बात भी जरूर उठती है। आपको पता है कि रुबिक क्यूब्स क्या होते हैं?

दोस्तों, तुम सभी ने आकार में चौकोर कई रंग-बिरंगे खानों वाला यह क्यूब कभी न कभी खेला जरूर होगा। उसे हल करना आमतौर पर लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इसीलिए उसे जो सही-सही खेल ले, वह बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। इस क्यूब को पसंद करने वालों में बहुत से ऐसे भी हैं, जो इसे सबसे जल्दी हल करने की प्रतियोगिता भी करते हैं। उन्हें 'स्पीड क्यूबर्स' के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग इसके लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भारत के भागीव नरसिम्हन। वह एक जाने-माने स्पीड क्यूबर हैं। उनके नाम रुबिक क्यूब के दो नेशनल रिकॉर्ड हैं और अब खबर है कि उन्होंने 5 रुबिक क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। यह उन्होंने एक मिनट के अंदर हल कर दिया। यह काम उन्होंने केवल एक हाथ से ही कर दिखाया। वैसे भागीव केवल 22 साल के हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर तुम भी रुबिक क्यूब्स को जल्द से जल्द हल करने का मुकाबला रख सकते हो। तुम्हें बहुत मजा आएगा।



अर्जुन से बदला लेने के लिए जब कर्ण के तूणीर में पहुंचा एक जहरीला सर्प

महाभारत से इतर भी हमें महाभारत के संबंध में कुछ कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा है कर्ण और सर्प के बारे में। लोककथाओं के अनुसार माना जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण के तूणीर में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सर्प आकर बैठ गया। तूणीर अर्थात जहां तीर रखते हैं, जिसे तरकश भी कहते हैं। यह पीछे पीठ पर बंधी होती है। कर्ण ने जब एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह यह सर्प उनके हाथ में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कहां से आ गए। तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तूणीर में जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों ? इस पर सर्प ने कहा, राजन! एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी, तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें। मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण-पखेरू उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी न रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। यह सुनकर सर्प वहां से उड़ गया। यदि कर्ण सर्प की बात मान लेते तो क्या होता ?

विंध्यचल पर्वत माला का पौराणिक महत्व

यह पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। विंध्य शब्द की व्युत्पत्ति ‘विध’ धातु से कही जाती है। भूमि को बेध कर यह पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है। यही मूल कल्पना इस नाम में निहित जान पड़ती है। विंध्य की गणना सप्तकुल पर्वतों में है। विंध्य का नाम पूर्व वैदिक साहित्य में नहीं है। इस पर्वत श्रंखला का वेद, महाभारत, रामायण और पुराणों में कई जगह उल्लेख किया गया है। विंध्य पहाड़ों की रानी विंध्यवासिनी माता है। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर (मिरजापुर, उप्र.) ब्रह्मलुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्यचल। विंध्यचल पर्वतश्रेणी पहाड़ियों की दूटी-फूटी श्रृंखला है, जो भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि का दक्षिणी कमार बनाती है। यह पर्वतमाला भारत के पश्चिम-मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रेणियां हैं, जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार तक लगभग 1,086 किमी तक विस्तृत फैला है। हालांकि इसकी कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को विकास का नाम पर काट दिया गया है। इन श्रेणियों में बहुमूल्य हीरे युक्त एक भूशीय पर्वत भी हैं।

इसकी प्रमुख नदियां : पहाड़ों के कटने से यहां से निकलने वाली नदियों का अस्तित्व भी संकट में है। विंध्य पर्वत में से उद्गम पाने वाली नदियां- शिप्रा या भद्रा (सिप्रा), पयोष्णी, निर्विंध्य (नेबुज), तापी निग्धा या निषधावती (सिंद), वेणवा या वेणा (वेणगंगा), वैतरणी (बैत्रणी), सिनीवाली या शिति बाहु, कुमुद्वती। (स्वर्ण रेखा), करतोषा या तोषा (ब्राह्मणी), महागौरी (दामोदर), और पूर्णा, शोण (सोन), महानद (महानदी) और नर्मदा। मध्यप्रदेश और गुजरात की सरकार में मिलकर सबसे बड़ी नर्मदा नदी की हत्या कर दी है। इस एक नदी के कारण संपूर्ण मध्यप्रदेश और गुजरात के जंगल हरे भरे और पशु पक्षी जीवंत रहते थे। लेकिन अब बाघ बनाकर एक ओर जहां नदी के जलचर जंतु मर गए हैं।

प्राकृतिक संपदा : भारत में पर्यावरण विनाश की सीमा अरावली पर्वत श्रेणियों और पश्चिम के घाटों तक ही सीमित नहीं है, मध्यक्षेत्र में भी बेतरतीब ढंग से जारी रहकर प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के कारण सतपुड़ा और विंध्यचल की पर्वत श्रेणियां तो खतरे में हैं ही अनेक जीवनदायी नदियों का वजूद भी संकट में है। वे लोग देशद्रोही है जो अपनी ही धरती को छलनी कर उसे विकास के नाम पर नष्ट कर रहे हैं।

पुराणों अनुसार : इसके अंतर्गत रोहतासगढ़, चुनारगढ़, कलिंजर आदि अनेक दुर्ग हैं तथा चित्रकूट, विन्ध्याचल आदि अनेक पावन तीर्थ हैं। पुराणों के अनुसार इस पर्वत ने सुमेरू से इंध्या रखने के कारण सूर्यदेव का मार्ग रोक दिया था और आकाश तक बढ़ गया था, जिसे अगस्त्य ऋषि ने नीचे किया। यह शरभंग, अगस्त्य इत्यादि अनेक श्रेष्ठ ऋषियों की तप :स्थली रहा है। हिमालय के समान इसका भी धर्मग्रंथों एवं पुराणों में विस्तृत उल्लेख मिलता है।

अगस्त्य मुनि : दक्षिण भारत और हिंदु महासागर से संबंधित अगस्ति (अगस्त्य) मुनि की गाथा है। उन्होंने विंध्यचल के बीच से दक्षिण का मार्ग निकाला। किविदंती है कि विंध्यचलपर्वत ने उनके चरणों पर झुककर प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा कि जब तक वे लौटकर वापस नहीं आते, वह इसी प्रकार झुका खड़ा रहे। वह वापस लौटकर नहीं आए और आज भी विंध्यचल पर्वत वैसे ही झुका उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।

विंध्यचल के जंगल : विंध्यचल पर्वत श्रेणियों के दोनों तरफ घने जंगल हैं, जो अब शहरी आबादी और विकास के चलते काट दिए गए हैं। अन जंगलों में शेर, चीते, भालु, बंदर, हिरणों के कई झुंड होते थे जो अब दूर बंदर हैं। अब चंबल, सतपुड़ा और मालवा के पठारी इलाके में ही कुछ जंगल बचे हैं। यहां की पर्वतों की कंदराओं में कई प्राचीन ऋषियों के आश्रम आज भी मौजूद हैं। यह क्षेत्र पहले ऋषि मुनियों का तप स्थल हुआ करता था। पर्वतों की कंदराओं में साधना स्थल, दुर्लभ शैल चित्र, पहाड़ों से अनवरत बहती जल की धारा, गहरी खाईयां और चारों ओर से घिरे घनघोर जंगलों पर अब संकट के बादल घिर गए हैं। यहीं पर भीम बैठका जैसी गुफाएं हैं।



शिवजी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्त्व है। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। यह प्राचीन परंपरा है। आइए जानते हैं शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित की जाती है। भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं, उतने ही रहस्यमयी भी हैं। भोलेनाथ का रहन-सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग हैं। शास्त्रों में एक ओर जहां सभी देवी-देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिवजी सदैव मृगचर्म (हिरण की खाल) धारण किए रहते हैं और शरीर पर भस्म (राख) लगाए रहते हैं। शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढंका रहता है। शिवपुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है, एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग (त्रैता युग, सत युग, द्वापर युग और कलियुग) के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्माजी द्वारा की जाती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिवजी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है। शिवपुराण के लिए अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है, उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिवजी को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वह सभी सुख-सुविधाएं प्राप्त करता है। शिवपुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान-सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी।

शिव को क्यों प्रिय है भस्म?



क्यों लगाते हैं भोलेनाथ शरीर पर भस्म, कैसे बनती है भस्मार्ती की भस्म

भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां हो रहे यज्ञ के हवनकुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेवैन हो गये। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के

महाकाल की भस्मार्ती

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्मार्ती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले श्मशान भस्म से भूतभावून भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती-श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधियुक्त उपलों में शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ीबूटी और कपूर-गुगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म ना सिर्फं सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे तीन प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कण्डे को जलाकर भस्म तैयार की हो वह लौकिक भस्म है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम धमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए ना जाने क्या-क्या करते हैं एक दिन इसी इस भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करता ही है तथा सब रोग कृपों को दूककर टंड और गमी से भी राहत दिलाती है। रोग कृपों के दंक जाने से शरीर की गमी बाहर नहीं निकल पाती इससे शीत का अहसास नहीं होता और गमी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गमी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं।

कैसे हुई भीष्म पितामह की पराजय

महाभारत युद्ध के दसवें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बीघने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया।

युधिष्ठिर को दिया धर्म ज्ञान

महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैल्या पर हैं। आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हो, उनके बारे में पूछ लीजिए। श्रीकृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए

तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। ऐसा कहकर भीष्मजी कुछ देर तक चुपचाप रहे। इसके बाद वे मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न-भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्मजी का प्राण उनके जिस अंग को त्यागकर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भी भर जाता। भीष्मजी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया,

इसलिए वह उनका मस्तक (ब्रह्म रंघ) फोड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार महात्मा भीष्म के प्राण आकाश में विलीन हो गए।



धुबरी में अजमल सुपर ४० की शानदार सफलता, ऑल इंडिया छएएढ परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान



सलीम शेख, धुबरी, १८ जुलाई: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धुबरी के अजमल सुपर ४० ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया छएएढ परीक्षा के प्रथम चरण के परिणाम में अजमल सुपर ४० के छात्रों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। संस्थान के अनुसार, ८० से अधिक छात्रों के कट-ऑफ अंक पार करने की संभावना है।प्रथम चरण के छएएढ परिणाम में धुबरी जिले का नाम रोशन करने वाले अजमल सुपर ४० के छात्रों का संस्थान के शिक्षकों ने सम्मान किया। धुबरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले सफल विद्यार्थियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर केक काटकर छात्रों ने खुशी का इजहार किया और जश्र मनाया।इसके बाद छएएढ में सफल सभी छात्रों के साथ एक विशाल रैली भी निकाली गई। सफल छात्रों ने अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। अजमल फाउंडेशन ने बताया कि इन सभी छात्रों को पूरी तरह से नि:शुल्क शैक्षणिक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अजमल सुपर ४०, धुबरी कैंपस ने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष ८० से अधिक छात्रों के छएएढकट-ऑफ पार करने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि पूरे असम में अजमल सुपर ४० के ७०० से अधिक विद्यार्थियों ने छएएढ परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

उधारबंद में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा, जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा क्षेत्र

नीहार कांति राय, उधारबंद १८ जुलाई : रथयात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। कभी उंचे-उंचे लकड़ी के रथ, रंग-विरंगी कागजी झालरों और पत्तों से सजे भव्य रथ, मिट्टी के खिलौनों से सजी मेले की रौनक तथा मोटी रस्सियों से रथ खींचने की सामूहिक परंपरा इस पर्व की विशेष पहचान हुआ करती थी। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की उमडती भीड़ आज भी लोगों की स्मृतियों को ताजा कर देती है। समय के साथ स्वस्‍य में कुछ बदलाव अवश्य आया है, लेकिन रथयात्रा की परंपरा और श्रद्धा आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है।इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुर्खार को उधारबंद में भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुई। रथयात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। सुबह से ही विभिन्न अखाडों और पूजा मंडपों में विशेष पूजा-अर्चना की गई तथा दोपहर में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद वितरित किया गया।

उधारबंद के कालाचांद अखाड़ा, दीप भट्टाचार्य के आवास तथा स्वगीय गौरी शर्मा के घर स्थित मंडप में श्रद्धालुओं की भारी भीड़.उमडी। शाम लगभग पांच बजे इन तीनों स्थानों से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को सुसज्जित रथों पर

मोबाइल और माइक लेकर कोई भी पत्रकार नहीं बन जाता, जवाबदेही भी जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (एजें) १८ जुलाई । दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए कहा है कि इसकी आड में गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि आज के समय में मोबाइल फोन और माइक्रोफोन लेकर कोई भी स्वयं को पत्रकार बताने लगता है, जबकि पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षण, नैतिकता और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक हैं।हाईकोर्ट ने कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के तेजी से विस्तार के बीच पत्रकारिता के नाम पर फजी, गैर-जिम्मेदाराना और डराने-धमकाने वाली गतिविधियां भी बढी हैं। ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अब सरकार को एक संतुलित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा ांचा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने और फजी या गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों पर जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल स्तंभ हैं, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही भी जुडी हुई है। इसलिए एक ऐसा संतुलित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता सुरक्षित रहे और उसके दुरु्योग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। मान्यता है कि रथयात्रा के दौरान भगवान के रथ नंदीघोष की रस्सी खींचने से भत्तों के पापों का क्षय होता है तथा उन्हें पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा से इस पावन आयोजन में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।

लखीमपुर में वन्यजीव हत्या और कुत्तों की तस्करी पर लगाम,ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग

लखीमपुर १८ जुलाई लखीमपुर जिले में वन्यजीवों और बेसहारा जानवरों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर पशु अधिकार कार्यकर्ता प्रिथमज्योति फ्कून ने १७ जुलाई २०२६ को लखीमपुर जिला ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गुनेंद्र डेका को एक स्मारक पत्र सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सौरापोशिव के जंगल में कुछ लोगों ने एक असहाय हिरन को मारकर उसके मांस के टुकड़े कर दिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ के तहत हिरन का शिकार दंडनीय अपराध है, जिसमें ३ से ७ साल तक की जेल का प्रावधान है। ३ जुलाई २०२६ को पूर्व तेलाही आदिवासी क्षेत्र में अजय ताईद नामक सदिष्ठ व्यक्ति को साइकिल पर बैग में बंद कुत्ते के साथ देखा गया। पूछताछ में उसने कुत्ते को सफाई के लिए ले जाने की बात कही। जांच में सामने आया कि कापाक चापरित क्षेत्र में कुछ लोग विभिन्न स्थानों से कुत्तों को लाकर अवैध रूप से मारकर मांस बेचते हैं। यह पशु कूरता निवारण अधिनियम १९६० का स्पष्ट उल्लंघन है।लखीमपुर शहर के खेलमाटी क्षेत्र में हाल ही में २ कुत्तों को चाकू से गोदकर और उबलता गर्म पानी डालकर मारने का प्रयास किया गया। इनमें से एक कुत्ते को गंभीर हालत में बचाकर पनिगांव सेंटर में भत्ती कराया गया है। संगठन का आरोप है कि नागलैंड से कुत्तों का मांस लाकर बेचने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। इससे पहले भी लखीमपुर पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था। स्मारक पत्र में विभिन्न मांग शामिल हैं जिसमें हिरन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी सौरापोशिव में हिरन की हत्या में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर कडी सजा दी जाए। अवैध तस्करी पर रोक गाय-भैंस चोरी.गाय-भैंस और कुत्ते के मांस की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह को पूरी तरह खत्म किया जाए। बाजारों में मवेशी विक्री के कागजात की जांच हो। गिरगनी बंदे शहर और जिले के संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त और उड्डत फुटेज की निगरानी की जाए। कुत्ते के मांस का कारोबार बंद हो कुत्तों को पकड़कर मांस के लिए बेचने वाले गिरोह को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। नागालैंड की तरफ कुत्तों की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा बढाई जाए। पुराने मामलों में कडी कार्रवाई लालुक थाने केस नं. ९७/२०२६ और सदर थाने केस नं. ४३५/२०२५ के आरोपियों को जमानत पर न छोड़ा जाए। संयुक्त अभियान गुवाहाटी पुलिस की तरह लखीमपुर पुलिस भी काबी आंगलॉग और अन्य इलाकों में अवैध तस्करी गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाए।पत्र में कहा गया है कि लखीमपुर से असम के अन्य जिलों तक फैले इस अंतरराज्यीय गिरोह को जल्द से जल्द ध्वस्त करना जस्री है, ताकि जिले में पशु कूरता पर पूरी तरह अंकुश लग सके।

उधारबंद में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा, जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा क्षेत्र



विराजमान कर शांभायात्रा निकाली गई।रथ की रस्सी खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरे मार्ग में 'जय जगन्नाथ' के जयघोष और संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। विभिन्न स्थानों पर रथ रोककर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम अर्पित किया।

रथयात्रा के दौरान किसी भी अग्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। उधारबंद के पुलिस अधिकारी चिरंजीव बरा के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रथयात्रा के दौरान प्रेरणा भारती से बातचीत में स्वगीय गौरी शर्मा स्मृति मंडप रथयात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष निरेशर सिंह (मना) ने बताया कि उनके मंडप का रथ कई दशक पुराना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के सहयोग और उत्साह के साथ रथयात्रा अत्यंत हषीछास एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।



DM GROUP





Resident Director
Our Products :
1. Derby Tea
2. Manipur Tea
3. Pathini Tea

Available At:
Regional Office: "Govind Bhawan", N.H.Road, P.O.: Chittaranjan Avenue, Silchar-788012, Assam, Ph: 03842-240913/213923

Registered Office:
" Continental Chambers", 4th Floor, 15A, H.B. Sarani, Kolkata-700001,W.B.

असम विधानसभा में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के आरोपों पर भाजपा ने अखिल गोगोई से मांगा जवाब

गुवाहाटी, १८ जुलाई (हि.स.)। राइजर दल के प्रमुख एवं शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई द्वारा संचालित काजीरंगा ऑर्फिंड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क में कथित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के मामले को लेकर असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को उन पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा और वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा द्वारा विधानसभा में लगाए गए गंभीर आरोपों का अखिल गोगोई अब तक स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब नहीं दे सके हैं।

प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने आरोप लगाया कि विधानसभा में मामला उठने के बाद भी अखिल गोगोई ने आरोपों का सीधा जवाब देने के बजाय मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर लगे आरोपों का तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए।मेधी ने दावा किया कि काजीरंगा ऑर्फिंड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क की वार्षिक आय लगभग १० से १२ करोड़ रुपये है, जिसमें से सात से आठ करोड़ रुपये केवल प्रवेश शुल्क से प्राप्त होते हैं।

अखिल भारतीय NEET परीक्षा में धुबरी के १२ छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन

सलीम शेख, धुबरी, १८ जुलाई: छएएढ प्रश्नपत्र लीक होने के बाद पहली परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई थी। स्वे विवाद और आंदोलनों के बीच आखिरकार बीती रात अखिल भारतीय छएएढ परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया।इस परिणाम में देशभर के साथ-साथ असम के धुबरी जिले के कुल १२ विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।धुबरी के हावरपारार निवासी एमडी तासीन मुत्ताकी सरकार ने ७२० में से ६८५ अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (अखट) २१३ हासिल की और जिले का गौरव बढ़ाया।वहीं, आर्थिक कठिनाइयों को मात देते हुए अजमल सुपर ४० के छात्र आरियन हुसैन ने ६५७ अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक १०२० हासिल की।गौरीपुर के एक

जीवन भर की कमाई समाज को समर्पित: सेवानिवृत्त प्रोफेसर दंपती ने विश्वविद्यालय को दान किए एक करोड़.

गुवाहाटी, १८ जुलाई (हि.स.)। त्याग, सादगी और समाजसेवा की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए कॉंटन कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. पञ्चालाल गोस्वामी और डॉ. नंदिता भट्टाचार्य गोस्वामी ने अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई एक करोड़ रुपये कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन



उनका आरोप था कि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के अनुसार इस आय पर प्रतिवर्ष लगभग १.५ करोड़ रुपये का जीएसटी देय होना चाहिए। भाजपा का दावा है कि पिछले आठ वर्षों में लगभग १२ से १५ करोड़ रुपये के जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया।भाजपा प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पार्क में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्राप्त आय का पूरा विवरण वार्षिक लेखा-जोखा में दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि यदि संस्था आर्थिक संकट में थी, जैसा कि अखिल गोगोई ने पहले दावा किया था, तो अतिरिक्त भूमि किस प्रकार प्राप्त की गई। उन्होंने इस विस्तार के लिए धन के स्रोत और भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की।मेधी ने अखिल गोगोई के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पार्क सरकार को सौंपने की बात कही थी। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि

से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेधी ने कहा कि यदि पार्क के सभी वित्तीय निर्णय उनकी जानकारी और स्वीकृति से होते रहे हैं, तो कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते।भाजपा ने पार्क की भूमि को लेकर भी सवाल उठाए। मेधी ने दावा किया कि प्रारंभ में पार्क के लिए २६ बीघा से अधिक भूमि स्वीकृत की गई थी, जबकि वर्तमान में इसका विस्तार १०० बीघा से अधिक क्षेत्र में हो चुका है। उन्होंने पूछा कि यदि संस्था आर्थिक संकट में थी, जैसा कि अखिल गोगोई ने पहले दावा किया था, तो अतिरिक्त भूमि किस प्रकार प्राप्त की गई। उन्होंने इस विस्तार के लिए धन के स्रोत और भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की।मेधी ने अखिल गोगोई के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पार्क सरकार को सौंपने की बात कही थी। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि

अखिल भारतीय NEET परीक्षा में धुबरी के १२ छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन



बडई के पुत्र लुत्फर अली ने ५९२ अंक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया।धुबरी धर्मशाला के अल रब्बी ने ५४२ अंक, जबकि तामाहाट क्षेत्र की जन्नत फिरदौसी ने ५३३ अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की।इसी प्रकार, धुबरी जिले के बिरसिंग क्षेत्र से भी कई विद्यार्थियों ने छएएढ परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बिरसिंग ग्राम पंचायत के मेहदी हसन ने ५७४ अंक, सातसिया गांव के फिरदौस अली ने ५६० अंक, फकीरांग के मेधावी छात्र रुवाई अल मुवाब्बस ने ५५४ अंक,

कटलामारी गांव की छात्रा मेहेजबीन अफसिन ने ५४३ अंक, मो. मुजाहारुल इस्लाम ने ५३८ अंक, जोसमिनारा परबीन ने ५३० अंक, सातसिया गांव की छात्रा आश्रुफा अहमद ने ५२५ अंक तथा फकीरांग के छात्र मस्दु अहमद ने भी ५२५ अंक प्राप्त किए। जानकारी के अनुसार, इन सफल विद्यार्थियों में अधिकांश परीक्षार्थी धुबरी जिले के चर (नदी द्वीप) क्षेत्रों से हैं। इन छात्रों की सफलता ने पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया है।

पार्क का संचालन करने वाली समिति के १० निदेशकों में से चार अखिल गोगोई के परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा या सरकार की ओर से पार्क पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और इस मुद्दे पर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्क के माध्यम से असम की विभिन्न जनजातीय और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण सराहनीय पहल है, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों की आड में कर नियमों के कथित उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। भाजपा ने मांग की कि यदि अखिल गोगोई पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखते हैं तो पूरे मामले के वित्तीय दस्तावेज सार्वजनिक करें।भाजपा ने विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए उस आरोप का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवसागर क्षेत्र के नामधरों में १.५ लाख रुपये नकद वितरित किए गए थे। मेधी ने कहा कि अखिल गोगोई इस आरोप पर भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता प्रांजल कलिता और मीडिया पैनलिस्ट कौशिक पाल दास भी उपस्थित थे।

दुमदुमा अंचल के फिलोबाडी में एक ही रात में तीन धार्मिक स्थलों पर चोरी

दुमदुमा प्रें. १८ जुलाई :-- दुमदुमा सम -जिला के अंतर्गत फिलोबाडी में कल रात तीन धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटना घटित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात फिलोबारी के बूनी शिव मंदिर , स्व्जान नामधर और गाभरुम्पेटी ११ नंबर वामुनागांव के काली मंदिर में चोरी की घटना हुई है। स्व्जान नामधर में चोरों के एक दल ने ताला तोड़कर मणिक्‍ट (गर्भगृह) के अंदर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने गर्भगृह के अंदर संदूक का ताला तोड़कर करीब ५० हजार रुपये लेकर फरार हो गए । चोरों ने गोदाम धर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया । नामधर प्रबंधन समिति ने इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर, गाभरुम्पेटी ११ नंबर वामुनागांव स्थित श्री श्री काली मंदिर में भी कल रात के समय चोरी की घटना हुई । चोरों ने काली मंदिर का दानपात्र तोड़कर नकदी लेकर रफूचक्कर हो गए। इसी बीच, फिलोबाडी बूनी स्थित श्री श्री शिव मंदिर का दानपात्र भी उसी रात चोरी हो गया। इसके साथ ही, फिलोबाडी विष्णुपुर के निवासी बाबुल कलिता की 'अड २३ छ २३०२' नंबर वाली फस्तर मोटरसाईकिल भी रात में चोरी हो गई । दुमदुमा अंचल में इन दिनों चोर मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पाँछले दिनों बड्ढापजान काली मंदिर में भी लाखों रूप्य की चोरी हुई थी । जिसमें आज तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है ।

PM-AJAY योजना के तहत १.१२ करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित अनुसूचित जाति के आत्मनिर्भरता अभियान को मिली नई गति

प्रीतम दास हाइलाकांदी, १८ जुलाई:अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (झच-अगअध) के अंतर्गत शनिवार को हाइलाकांदी के रवीन्द्र भवन सभागार में एक भव्य अनुदान वितरण समारोह का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला आयुक्त जय विकास तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हाइलाकांदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. मिलन दास उपस्थित रहे।यह कार्यक्रम जिला मिशन प्रबंधन इकाई (ज्वचवर्ग) असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (अडछड) तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।समारोह में जिले के १८५ अनुसूचित जाति स्वयं सहायता समूहों (डड उव्वर्रै) को अनुदान राशि प्रदान की गई। इसके अलावा ४३ स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यक्तिगत वित्तीय सहायता भी दी गई। इस प्रकार हैलाकांडी जिले में कुल १ करोड़.१२ लाख ३८ हजार रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई।अपने संबोधन में विधायक डॉ. मिनन दास ने कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इस योजना से स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा छोटे-छोटे उद्यम स्थापित करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है बल्कि लाभार्थियों के लिए स्थायी आय के स्रोत विकसित कर उन्हें वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बनाना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और समाज के वंचित वर्गों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा।डॉ. मिलन दास ने आगे कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही हैं। झच-अगअध ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है जो अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएज) जिला परिषद की अध्यक्ष फातिमा बेगम चौधरी अलगापुर कटलीछड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि सैदुल इस्लाम बरमुड्या विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जनप्रतिनिधि तथा बडी संख्या में स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उपस्थित थे।जिला प्रशासन ने बताया कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झच-अगअध के अंतर्गत यह अनुदान वितरण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वामी श्री दिलीप कुमार द्वारा भारती ऑफसेट मुद्रणालय, कटहल रोड, शिलचर-05 (असम) से

मुद्रित व प्रकाशित, सम्पादक-श्रीमती सीमा कुमार, Ph & Fax (03842) 242633, (M) 9435213512